भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3718
जिसका उत्तर बुधवार, 05 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

उद्योगों का विकास

3718. श्री पि. भट्टाचार्य:
श्रीमती रजनी पाटिल:
श्री दर्शन सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में भारी अभियांत्रिकी उपकरण, मशीन कलपुर्जों, स्वचालित तथा विद्युत उपकरण क्षेत्र के विकास तथा वृद्धि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या उक्त उद्योगों के विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में उक्त क्षेत्र के विकास तथा वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख):

(₹ करोड़ में)

केपिटल गुड्स के सेगमेंट	उत्पादन (₹ करोड़ में) और वार्षिक प्रतिशत वृद्धि (%)		
	2013-14	2014-15	2015-16
मशीन टूल्स लिमिटेड	3,481 -10.40%	4,230 21.52%	4,727 11.75%
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	16,000 -3.61%	17,000 6.25%	19,375 13.97%
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट	128,823- 4.13%	136,953 6.31%	144,861 5.77%

(स्रोत: उद्योग संघ)

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) द्वारा सूचित की गई ऑटोमोबाइल उद्योग के उत्पादन में वृद्धि निम्नानुसार है:-

(सं. हजार यूनिट में)

2013-14	2014-15	2015-16
21,500	23,358	23,960

(ग): केपिटल गुड्स उद्योग जिसमें इसके उप-सेक्टर जैसे कि मशीन औजार, अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी तथा हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शामिल हैं, के लिए ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए भी ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ परामर्श करके ऑटोमोबाइल मिशन प्लान के रूप में विकास पथ की परिकल्पना की है। इस तरह की योजना सर्वप्रथम 2006 में 10 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ की गई थी। इस स्कीम का निष्पादन निम्नवत हैं:-

- भारत में बहुतायत में स्थानीय और वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माता तथा कलपुर्जा विनिर्माता आकर्षित हुए, जिससे लक्ष्य से अधिक ₹1,57,500 करोड़ हासिल हुए।
- यद्यपि वाणिज्यिक वाहनों, यात्री वाहनों और ट्रैक्टरों की संचयी घरेलू बिक्री का लक्ष्य हासिल हुआ, दुपहिया और तिपाहिया वाहनों की बिक्री लक्ष्य से कम रह गई।

(घ): भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि के लिए सरकार ने नवंबर, 2014 में एक स्कीम शुरू की जिसमें (1) प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, (2) एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा अर्थात् औद्योगिक पार्क, (3) साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र, और (4) परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की स्थापना जैसे अवसंरचनात्मक संघटक शामिल हैं। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति/हस्तांतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निधि कार्यक्रम के द्वारा वित्तीय हस्तक्षेप का प्रावधान भी शामिल है। इस स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत अभी तक 14 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत हाल ही में इस वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का शुभारंभ किया है। इस स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

जहां तक, ऑटोमोबाइल सेक्टर का संबंध है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया स्कीम का शुभारंभ और नेट्रिप परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक वाहन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना।

*****